नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 164
दि. 19.03.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

प्रेम विवाह पर सामाजिक टकराव: गुजरात से राजस्थान तक परंपरा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जंग तेज

(जीएनएस)। अहमदाबाद से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक इन दिनों प्रेम विवाह को लेकर एक ऐसा विवाद सामने आया है, जिसने समाज, परंपरा और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच गहरे टकराव को उजागर कर दिया है। गुजरात की चर्चित लोक गायिका किंजल रबारी और राजस्थान के राजनीतिक परिवार से जुड़े मानवेंद्र सिंह जसोल के प्रेम विवाह ने दो अलग-अलग राज्यों में सामाजिक उबाल पैदा कर दिया है। यह मामला केवल दो व्यक्तियों के निजी जीवन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह अब जातीय पहचान, पारंपरिक मान्यताओं और आधुनिक सोच के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गया है।

गुजरात के बनासकांठा जिले के राधनपुर क्षेत्र में रहने वाली किंजल रबारी, जो रबारी समुदाय से संबंध रखती हैं, ने अपने मित्र अशोक चौधरी के साथ अंतरजातीय विवाह कर लिया। यह विवाह जैसे ही सार्वजनिक हुआ, उनके परिवार और समाज में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। किंजल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बताया था कि उन्होंने अपनी मर्जी से विवाह किया है, लेकिन इसके बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने राज्य के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और विधानसभा अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी से हस्तक्षेप की मांग भी की थी। हालांकि बाद में परिवार के दबाव के चलते उन्हें वापस पिता के घर लाया गया, जहां से उन्होंने एक और वीडियो जारी कर लोगों से अपील की कि उनके परिवार को बदनाम न किया जाए।

किंजल के पिता ठाकरशी रबारी ने भी स्पष्ट किया कि वे अपनी बेटी का विवाह अपने ही समुदाय में करना पसंद करेंगे, लेकिन किसी अन्य समाज में विवाह को स्वीकार नहीं कर सकते। यह बयान उस पारंपरिक सोच को दर्शाता है, जिसमें जातीय सीमाएं आज भी विवाह जैसे व्यक्तिगत निर्णयों पर भारी पड़ती हैं। इसी तरह का एक और मामला पश्चिमी राजस्थान में सामने आया है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल के पुत्र मानवेंद्र सिंह जसोल ने चारण समाज की युवती नीरजा से प्रेम विवाह कर लिया। जैसे ही इस विवाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, चारण समाज में तीव्र विरोध शुरू हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि जब मानवेंद्र अपनी पत्नी के साथ अपने पैतृक आवास पहुंचे, तो उनकी मां शीतल कंवर और पुत्र हम्मीर ने उन्हें घर में प्रवेश करने से रोक दिया। यहां तक कि हवेली के बाहर लगी उनकी नेम प्लेट भी हटा दी गई, जो इस विरोध का प्रतीक बन गई।

चारण समाज के वरिष्ठ नेता सीडी देवल ने इस विवाह पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे समाज और परंपरा के खिलाफ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम से न केवल चारण समाज की मर्यादा को ठेस पहुंची है, बल्कि राजपूत समुदाय की परंपराओं को भी आघात लगा है। देवल ने यह मामला देश के शीर्ष नेताओं जैसे नरेन्द्र मोदी और अमित शाह के समक्ष उठाने की बात कही है और मानवेंद्र को राजनीतिक दल से बाहर करने की मांग भी की है।

इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज के समय में भी व्यक्ति को अपने जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता पूरी तरह से प्राप्त है, या फिर समाज और परंपरा की सीमाएं अब भी उस पर हावी हैं। एक ओर जहां युवा पीढ़ी अपनी पसंद और भावनाओं को प्राथमिकता दे रही है, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक समाज अपनी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपनाए हुए है।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच हर्ष संघवी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत प्रस्ताव भी चर्चा में है, जिसमें प्रेम विवाह के मामलों में माता-पिता को तुरंत सूचना देने और ऐसे विवाहों पर व्यापक सामाजिक एवं कानूनी विमर्श की बात कही गई है। कई समुदायों के नेताओं ने तो यहां तक मांग कर दी है कि प्रेम विवाह के लिए माता-पिता की सहमति को अनिवार्य बनाया जाए।

यह विवाद केवल गुजरात और राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में चल रहे उस व्यापक सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा है, जिसमें परंपराओं और आधुनिक मूल्यों के बीच संतुलन खोजने की कोशिश जारी है। जहां एक ओर संविधान व्यक्ति को अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार देता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक दबाव और पारिवारिक अपेक्षाएं इस अधिकार को व्यवहार में सीमित कर देती हैं।

इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया अभी अधूरी है। प्रेम विवाह जैसे व्यक्तिगत निर्णय भी सामूहिक पहचान और परंपराओं से टकरा जाते हैं, जिससे कई बार तनाव और विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में जरूरत है संवाद और समझ की, ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके और समाज एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सके।

बजट सत्र के बीच दहशत: गुजरात विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर

(जीएनएस)। गुजरात में चल रहे बजट सत्र के बीच उस समय हड़कंप मच गया, जब गुजरात विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी ऐसे समय पर आई जब सदन की कार्यवाही शुरू होने में महज कुछ मिनट बाकी थे, जिससे पूरे प्रशासनिक तंत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा एजेंसियां तत्काल हरकत में आ गईं।

अधिकारियों के अनुसार, बुधवार सुबह ईमेल के जरिए यह धमकी भेजी गई, जिसमें दावा किया गया था कि विधानसभा परिसर में बम लगाया गया है। जैसे ही यह सूचना सामने आई, तुरंत एहतियात के तौर पर पूरे परिसर को खाली कराया गया। वहां मौजूद सभी विधायक, कर्मचारी और अन्य स्टाफ को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। मामले की जानकारी देते हुए पीयूष वांडा ने बताया कि सदन की कार्यवाही सुबह 9 बजे शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले करीब 8:45 बजे अधिकारियों को इस धमकी भरे ईमेल की सूचना मिली। समय की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और बम निरोधक दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा और पूरे परिसर को अपने कब्जे में लेकर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

सुरक्षा एजेंसियों ने विधानसभा भवन के हर

हिस्से—सदन कक्ष, कार्यालयों, पार्किंग एरिया और आसपास के संवेदनशील स्थानों—की बारीकी से जांच की। इस दौरान डॉग स्क्वॉड और बम डिटेक्शन टीमों की भी मदद ली गई, ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु को समय रहते पहचानकर निष्क्रिय किया जा सके। हालांकि शुरुआती जांच में अब तक कोई विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है, लेकिन एहतियात के तौर पर जांच प्रक्रिया जारी रखी गई है।

इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विधानसभा जैसे अति-संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थल पर इस तरह की धमकी मिलना न केवल राज्य की सुरक्षा के लिए चुनौती है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि असामाजिक तत्व किस तरह तकनीक का इस्तेमाल कर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ईमेल के जरिए धमकी भेजना यह संकेत देता है कि साइबर ट्रैकिंग और डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

घटना के बाद पुलिस ने तुरंत ईमेल के स्रोत का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साइबर क्राइम की टीम इस बात की जांच कर रही है कि यह मेल कहां से भेजा गया और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की धमकियां अक्सर अफवाह या शरारत भी हो सकती हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से किसी भी सूचना को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

इस बीच, विधानसभा परिसर के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और आने-जाने वाले हर व्यक्ति की सघन जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और सख्त प्रोटोकॉल लागू किए जाएं।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी इस घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है। विधायकों और अधिकारियों ने इसे सुरक्षा के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा है और मांग की है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

हालांकि अब तक कोई विस्फोटक नहीं मिलने से राहत की बात सामने आई है, लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि सतर्कता में जरा सी भी ढील भारी पड़ सकती है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह चौकन्नी हैं और हर पहलू की गहराई से जांच कर रही हैं, ताकि इस धमकी के पीछे छिपे सच का पता लगाया जा सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

गैस संकट में इंसानियत की मिसाल: सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने मजदूरों के लिए खोला 'मेगा किचन', 24 घंटे मिल रहा भोजन

(जीएनएस)। सूरत। औद्योगिक शहर सूरत में इन दिनों गैस संकट ने आम जनजीवन के साथ-साथ हजारों प्रवासी मजदूरों के सामने भी गंभीर चुनौती खड़ी कर दी थी, लेकिन इस कठिन समय में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने जिस तरह आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाई है, वह एक मिसाल बनकर सामने आई है। पांडेसरा, सचिन और पलसाना जैसे औद्योगिक इलाकों में काम करने वाले मजदूरों के लिए खाना बनाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि बाजार में गैस सिलेंडर की भारी कमी थी और जो उपलब्ध थे, वे भी महंगे दामों पर मिल रहे थे। ऐसे हालात में मजदूरों के सामने दो ही रास्ते बचे थे—या तो भूखे रहना या फिर अपने गांव लौट जाना। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों ने तुरंत पहल की और पांडेसरा क्षेत्र में एक बड़े स्तर पर 'मेगा किचन' शुरू कर दिया। यह केवल एक अस्थायी व्यवस्था नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित और मानवीय प्रयास है, जिसमें हर दिन हजारों मजदूरों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पहले जहां एक सामान्य रेस्टोरेंट में 1000 से 1500 लोगों के लिए खाना बनता था, वहीं अब उसी स्थान को पूरी तरह बदलकर रोज़ाना 4000 से 5000 मजदूरों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है।

इस मेगा किचन की सबसे खास बात यह है कि यह 24 घंटे संचालित हो रहा है। इसका मतलब यह है कि किसी भी शिफ्ट में काम करने वाला मजदूर कभी भी आकर भोजन कर सकता है। यहां भोजन की कीमत भी केवल 50 रुपये रखी गई है, ताकि हर वर्ग का मजदूर इसे आसानी से वहन कर सके। भोजन पूरी तरह सात्विक और पौष्टिक रखा गया है, जिससे मजदूरों की सेहत पर भी सकारात्मक असर पड़े।

किचन के प्रबंधन से जुड़े हसमुख ठक्कर बताते हैं कि अचानक बढ़ी मांग को देखते हुए किचन की क्षमता कई गुना बढ़ानी पड़ी। प्रतिदिन करीब 1000 मजदूर बैठकर भोजन करते हैं, जबकि बाकी मजदूरों के लिए पैक्ड फूड की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही 'मील-टू-मील' सेवा भी शुरू की गई है, जिसके तहत विभिन्न फैक्ट्रियों और यूनिट्स तक सीधे भोजन के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। इससे मजदूरों को काम छोड़कर बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती और उनका समय भी बचता है।

इस पहल का सबसे बड़ा असर यह हुआ है कि मजदूरों का पलायन रुक गया है। कई मजदूर जो अपने गृह राज्य लौटने की सोच रहे थे, उन्होंने अब शहर में ही रुकने का फैसला किया है। एक मजदूर ने बताया कि गैस की कमी के कारण खाना बनाना लगभग असंभव हो गया था और बाहर खाना बहुत महंगा पड़ रहा था। ऐसे में इस किचन ने उन्हें न केवल भोजन दिया, बल्कि मानसिक राहत भी दी है।

टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह केवल एक व्यावसायिक शहर नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह है, जहां संकट के समय सभी एक-दूसरे का साथ देते हैं। दक्षिण गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जीतू वखारिया ने कहा कि इंडस्ट्री हमेशा मजदूरों के साथ खड़ी रहती है, क्योंकि यही मजदूर इस शहर की असली ताकत हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, यह व्यवस्था जारी रहेगी।

सुबह से लेकर देर रात तक किचन के बाहर मजदूरों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं, लेकिन पूरे सिस्टम को इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि किसी को असुविधा न हो। अतिरिक्त स्टाफ, साफ-सफाई, अनुशासन और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिससे यह पहल केवल राहत नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित मॉडल के रूप में उभर रही है।

गैस संकट जैसे कठिन समय में सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने यह साबित कर दिया है कि उद्योग केवल मुनाफे के लिए नहीं होते, बल्कि समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। यह 'मेगा किचन' न सिर्फ भूख मिटा रहा है, बल्कि हजारों मजदूरों के जीवन में भरोसा और स्थिरता भी लौटा रहा है।

तेज़ रफ्तार भारत की ओर बड़ा कदम: सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का ढांचा तैयार, अब फिनिशिंग और ट्रैक कार्य तेज़

(जीएनएस)। सूरत में देश की बहुप्रतीक्षित हाई-स्पीड रेल परियोजना को लेकर बड़ी प्रगति सामने आई है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी ताज़ा प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के तहत बन रहे सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का मुख्य स्ट्रक्चरल कार्य लगभग पूरा हो चुका है। स्टेशन भवन का स्टील स्ट्रक्चर और रूफ शीटिंग का काम समाप्त होने के साथ ही अब परियोजना अपने अगले महत्वपूर्ण चरण—फिनिशिंग और ट्रैक बिछाने—की ओर तेज़ी से बढ़ रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, स्टेशन परिसर में फॉल्स सीलिंग, दीवारों और कॉलम की क्लैडिंग, प्लेटफॉर्म और कॉनकोर्स एरिया की फ्लोरिंग जैसे आंतरिक कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। साथ ही, रेलवे ट्रैक बिछाने का काम भी समानांतर रूप से जारी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि परियोजना अब अंतिम चरणों की ओर अग्रसर है। निर्माण एजेंसियां समयसीमा को ध्यान में रखते हुए दिन-रात काम कर रही हैं, ताकि स्टेशन को निर्धारित समय में तैयार किया जा सके।

इस परियोजना की एक खास विशेषता इसका मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन (MMI) है, जिसे यात्रियों के लिए बेहद सुविधाजनक बनाया जा रहा है। एनएचएसआरसीएल ने सूरत के अलावा बिल्लीमोरा, वापी, भरूच, आनंद और वडोदरा जैसे प्रमुख स्टेशनों के लिए भी स्टेशन एरिया डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन के कॉन्ट्रैक्ट पहले ही जारी कर दिए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्रियों को एक ही स्थान पर बस, टैक्सी, निजी वाहन और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों की सुविधा मिल सके।

लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए स्टेशन के आसपास आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। इसमें पार्किंग एरिया, पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ ज़ोन, पैदल यात्रियों के लिए चौड़े फुटपाथ, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, स्पष्ट साइनेज सिस्टम और अत्याधुनिक सीसीटीवी निगरानी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा, स्टेशन परिसर को आकर्षक बनाने के लिए लैंडस्केपिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि यात्रियों को एक विश्वस्तरीय अनुभव मिल सके। सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को भी इस परियोजना में प्राथमिकता दी गई है। फायर फाइटिंग सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट और आधुनिक सुरक्षा मानकों के अनुरूप डिज़ाइन किए गए ढांचे से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्टेशन न केवल सुविधाजनक हो, बल्कि पूरी तरह सुरक्षित भी हो।

यदि अन्य स्टेशनों की प्रगति पर नजर डालें तो बिल्लीमोरा, वापी और भरूच में स्लैब कास्टिंग और स्टील स्ट्रक्चर का काम पूरा हो चुका है, जबकि आर्किटेक्चरल फिनिशिंग और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन तेजी से जारी हैं। आनंद स्टेशन पर रूफ शीटिंग के साथ-साथ लिफ्ट और एस्केलेटर की स्थापना भी पूरी हो चुकी है, जबकि वडोदरा में बहु-स्तरीय निर्माण कार्य अलग-अलग चरणों में आगे बढ़ रहा है।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। यह परियोजना न केवल यात्रा के समय को बेहद कम कर देगी, बल्कि देश में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क की नींव भी मजबूत करेगी। सूरत जैसे औद्योगिक शहर के लिए यह स्टेशन व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी के नए अवसर खोलने वाला साबित हो सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी और आसपास के शहरों के बीच आवागमन बेहद आसान हो जाएगा। इससे न केवल आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का स्ट्रक्चरल कार्य पूरा होना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो यह दर्शाता है कि भारत अब आधुनिक और तेज़ परिवहन व्यवस्था की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। आने वाले समय में जब यह परियोजना पूरी तरह से शुरू होगी, तब यह देश की प्रगति और तकनीकी क्षमता का एक शानदार उदाहरण बनकर सामने आएगी।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

पंजाब के प्राकृतिक सुरक्षा कवच पर चोट

सत्ताधीशों की इच्छा शक्ति की कमी और प्रवर्तन एजेंसियों की लापरवाही से खनन माफिया के हौसल बुलंद हैं। कहीं न कहीं नागरिकों की उदासीनता भी इसके मूल में हैं। पंजाब के रोपड़ जिले की शिवालिक पहाड़ियों में हो रही तबाही उस भयावह स्थिति को दर्शाती है, जिसका खमियाजा आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। वजह साफ है कि अंधाधुंध खनन से शिवालिक पहाड़ियों के पारिस्थितिकीय तंत्र को भारी क्षति पहुंच रही है। जो हमें यह भी बताता है कि नीति और प्रवर्तन के बीच खाई में पर्यावरणीय अपराध कैसे और किस तेजी से पनपते हैं। प्रशासन की नाक के नीचे खुदाई करने वाली भारी मशीनों का खुलेआम प्रयोग अवैध खनन हेतु किया जा रहा है। इस पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र की पूरी पहाड़ियों को समतल किया जा रहा है। जो हमारे पर्यावरण के लिये एक गंभीर चुनौती है। यह क्षति शिवालिक पहाड़ियों के मूल पारिस्थितिक कार्यों मसलन भूजल पुनर्भरण, मृदा-स्थिरता और जैव-विविधता संरक्षण जैसे जीवन रक्षक लक्ष्यों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। दरअसल, यह शिवालिक पर्वतमाला भू-संरचना की दृष्टि से नयी बनी हुई है और स्वाभाविक रूप से अस्थिर है। निर्विवाद रूप से किसी भी स्थान पर होने वाली अनियंत्रित खुदाई से भूमि का कटाव बहुत तेजी से होता है। जिसके चलते वर्षा ऋतु और उसके बाद भूस्खलन की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती है। वहीं इन क्षेत्रों में गाद जमाव का संकट भी गहरा जाता है। कालांतर इसके चलते जल निकासी के पैटर्न में अप्रत्याशित बदलाव देखने में आता है। यह सर्वविदित है कि एक बार इन पहाड़ियों को अवैध रूप से काटकर समतल कर दिया जाता है तो उसके मूल स्वरूप को फिर प्राप्त कर पाना लगभग असंभव है। दूसरे शब्दों में कहें उस क्षेत्र विशेष का प्राकृतिक संरक्षण कवच हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। ऐसे में प्राकृतिक सुरक्षा को नष्ट करने वाला विकास कालांतर आपदा का कारक बन सकता है।

दरअसल, यह ऐसा प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र होता है जो निचले मैदानी इलाकों को बाढ़ और जल संकट से बचाता है। यह विडंबना ही कही जाएगी कि इस बाबत जवाबदेह अधिकारियों द्वारा दलील दी जाती रही है कि इस क्षेत्र में खनन की प्रक्रिया पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों के आधार पर की जाती रही है। साथ ही यह भी सफाई दी जाती है कि ऐसी स्वीकृतियों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन हकीकत तब उजागर हो जाती है जब स्थानीय लोग रात के समय होने वाले खनन कार्यों, निर्धारित सीमा से अधिक और बड़े पैमाने पर पहाड़ी इलाकों में कटाई होने के आरोप लगाते हैं। ऐसे में अधिकारियों की तमाम दलीलें खोखली ही साबित होती हैं। दरअसल,सवाल नियम-कानूनों की प्रभावकारिता का नहीं है बल्कि असली दिक्कत प्रवर्तन एजेंसियों की उदासीनता की है। जो वस्तु-स्थिति से अवगत होने के बावजूद इन आपराधिक कृत्यों के प्रति आंखें मूंदे रहती हैं। दरअसल, खनन कार्यों से जुड़े ठेकेदारों को आपराधिक तत्वों व राजनेताओं का संरक्षण भी एक बड़ी चुनौती है। इसमें दो राय नहीं है कि जब अवैध खनन के खिलाफ जमीनी स्तर पर निगरानी के बजाय महज कागजी कार्रवाई का सहारा लिया जाता है तो अवैध खनन को संबल मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि यह अवैध खनन केवल पंजाब की शिवालिक पहाड़ियों के आसपास ही हो रहा है। पूरे भारत में, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तमाम क्षेत्रों में अवैध खनन लगातार पर्यावरण से जुड़े कानूनों की सीमाओं का उल्लंघन करता नजर आता है। अकसर खनन के लिये दिए गए परमिटों में अस्पष्टता और स्थानीय स्तर पर कमजोर निगरानी का फायदा उठाया जाता है। वह भी तब जब सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के फैसलों में बार-बार इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि आर्थिक गतिविधियां पारिस्थितिकीय नुकसान की कीमत पर नहीं चलायी जा सकती। फिर भी, जमीनी स्तर पर, प्रवर्तन एजेंसियां या तो शक्तिहीन दिखाई देती हैं या निर्णायक कार्रवाई करने की इच्छाशक्ति उनमें नजर नहीं आती। वास्तव में अवैध खनन पर सिर्फ जुर्माना लगाने के बजाय प्रतिबंधित क्षेत्रों का सख्त सीमांकन, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी तथा अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत है।

संस्मरण की सशक्त आवाज़ को मिला सम्मान

> संस्मरण-पुस्तक के बहाने यह सम्मान ममता जी के उस दीर्घ साहित्यिक यात्रा का भी सम्मान है, जिसमें उन्होंने लगभग छह दशकों तक निरंतर लेखन करते हुए हिंदी कथा-साहित्य और स्त्री-लेखन को नई दृष्टि प्रदान की है।

हिंदी साहित्य की बहुआयामी और सशक्त रचनाकार ममता कालिया को उनके चर्चित संस्मरण जीते जी इलाहाबाद (2021) के लिए वर्ष 2025 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाना हिंदी साहित्य जगत के लिए एक सुखद क्षण है।

2 नवम्बर, 1940 को उत्तर प्रदेश के वृंदावन में जन्मी ममता कालिया हिंदी साहित्य की उन रचनाकारों में हैं जिनकी रचनात्मकता किसी एक विधा तक सीमित नहीं रही। कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, निबंध, संस्मरण और पत्रकारिता के साथ लगभग हर विधा में उन्होंने अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है। हिंदी कहानी के परिदृश्य पर उनका लेखन सातवें दशक से लगातार सक्रिय रहा है और लगभग आधी सदी के रचनात्मक काल में उन्होंने दो सौ से अधिक कहानियां लिखीं, जो समकालीन जीवन की विडंबनाओं, मध्यवर्गीय संघर्षों और स्त्री-अनुभवों की सजीव अभिव्यक्ति हैं। साहित्यिक संस्कार वाले उस परिवार में ममता जी जन्मी जहां, पिता विद्याभूषण अग्रवाल हिंदी और अंग्रेज़ी साहित्य के विद्वान तथा शिक्षक थे। शिक्षा और जीवन के विभिन्न चरणों में भारत के कई शहरों में रहना उनके व्यक्तित्व और लेखन को व्यापक सामाजिक अनुभवों से समृद्ध करता रहा। तभी उनकी रचनाओं में भारतीय शहरी जीवन का यथार्थ, बदलते पारिवारिक संबंध और स्त्री की आत्मसजगता गहरे रूप में दिखाई देती है। कहानी के क्षेत्र में ममता कालिया की विशिष्ट पहचान है। उनकी संपूर्ण कहानियां अब तक ममता कालिया की कहानियां (2017) शीर्षक से दो खंडों में प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके चर्चित कहानी संग्रहों में छुटकारा, एक अदद औरत, सीट नं. छह, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन, मुखौटा, निर्मोही, थिएटर रोड के कौए और पच्चीस साल की लड़की विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन कहानियों में समकालीन जीवन की विसंगतियां, मध्यवर्गीय परिवारों के अंतर्विरोध और स्त्री की आत्मसंघर्षशील चेतना सशक्त रूप में उभरती है।

उपन्यास विधा में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण है। बेघर (1971), नरक दर नरक (1975), प्रेम कहानी (1980), लड़कियां (1987), एक पत्नी के नोट्स (1997), दौड़ (2000), अंधेरे का ताला (2009), दुक्खम्–सुक्खम् (2009), कल्चर वल्चर (2016) और सपनों की होम डिलीवरी (2017) जैसे उपन्यास हिंदी कथा साहित्य की उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। इनमें बदलते सामाजिक मूल्य, उपभोक्तावादी संस्कृति और स्त्री की बदलती भूमिकाएं अत्यंत संवेदनशील ढंग से चित्रित हुई हैं। कविता, नाटक और संस्मरण लेखन में भी ममता कालिया ने अपनी अलग पहचान बनाई। उनके कविता संग्रहों में खांटी घरेलू औरत और कितने प्रश्न करूं उल्लेखनीय हैं। नाटकों में यहां रहना मना है और आप न बदलेंगे चर्चित रहे हैं। संस्मरण विधा में उनकी पुस्तक कितने शहरों में कितनी बार (2010) और नवीनतम जीते जी इलाहाबाद पाठकों और आलोचकों दोनों के बीच विशेष रूप से सराही गई है।

सीधे-सीधे संस्मरण जीते जी इलाहाबाद की बात करें तो पाते हैं कि एक लेख से शुरू हुए इस पुस्तक के पूर्ण होने की यात्रा में एक शहर की स्मृतियों का आख्यान होने के साथ-साथ साहित्यिक और सांस्कृतिक परिवेश की जीवंत झांकी भी है, जिसमें इलाहाबाद (अब प्रयागराज) की बौद्धिक परंपरा और रचनात्मक वातावरण को आत्मीयता से दर्ज किया गया है। यानी ममता कालिया ने संस्मरण विधा को निजी स्मृतियों के कथन से आगे ले जाकर उसे एक व्यापक सांस्कृतिक और साहित्यिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ा है। यह कृति किसी एक व्यक्ति के जीवन का वृत्तांत न होकर उस साहित्यिक शहर की जीवित स्मृति है, जिसने आधुनिक हिंदी साहित्य को दिशा दी। ममता कालिया ने शहर के उस वातावरण को पुनर्सृजित किया है जहां साहित्य, संवाद और बौद्धिक बहसें जीवन का स्वाभाविक हिस्सा थीं। वे बताती हैं कि यहां पैदल चलना किसी विवशता का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मीय सामाजिक जीवन का संकेत था। इस शहर की सांस्कृतिक संरचना में लेखकों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की सक्रिय उपस्थिति थी, जिसने उसे हिंदी साहित्य की उर्वर भूमि बना दिया।

संस्मरण का एक महत्वपूर्ण पक्ष इसका शब्द चित्रात्मक शिल्प है। इसमें उपेन्द्रनाथ अश्क, नरेश मेहता, अमरकांत, ज्ञानरंजन, दूधनाथ सिंह और रवीन्द्र कालिया जैसे साहित्यकारों के जीवंत चित्र मिलते हैं, जो उस दौर की साहित्यिक संस्कृति को मूर्त रूप देते हैं। इन चित्रों में प्रशंसा के साथ मानवीय कमजोरियों का भी सहज उल्लेख है, जिससे संस्मरण की विश्वसनीयता और बढ़ जाती है। इस प्रकार जीते जी इलाहाबाद एक ऐसे साहित्यिक नगर का सांस्कृतिक दस्तावेज़ है जो रचनात्मकता, प्रतिरोध और आत्मीयता की परंपरा को जीवित रखता है।

वर्ष 2017 में ममता जी को उपन्यास दुक्खम्–सुक्खम् के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त साहित्य भूषण सम्मान, यशपाल स्मृति सम्मान, सावित्री बाई फुले स्मृति सम्मान और लमही सम्मान जैसे अनेक अलंकरण उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। अब 2025 में जीते जी इलाहाबाद के लिए मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी साहित्यिक साधना की एक महत्वपूर्ण स्वीकृति है।

लेखक दिल्ली विवि. में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।

प्रेरणा

जब दृष्टिकोण बदलता है तो समस्या स्वयं सुलझ जाती है

जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक यह है कि समस्याएँ अक्सर उतनी जटिल नहीं होतीं, जितना हम उन्हें बना लेते हैं। कई बार उलझन का कारण परिस्थिति नहीं, बल्कि हमारी सीमित सोच होती है। जब हम किसी समस्या को केवल एक ही कोण से देखते हैं, तो वह असंभव प्रतीत होती है, लेकिन जैसे ही हम दृष्टिकोण बदलते हैं, समाधान स्वयं सामने आ जाता है। इसी गहन सत्य को एक सूफी संत और उनके तीन शिष्यों की कथा अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है।

एक सूफ़ी संत थे, जिनके तीन शिष्य थे। ये तीनों अपने गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धावान थे और वर्षों से उनके साथ रहकर ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। संत भी अपने शिष्यों से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि संसार की सबसे मजबूत डोर भी संपत्ति के प्रश्न पर कमजोर पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने अपने जीवनकाल में ही इस विषय को सुलझाने का निर्णय लिया, ताकि उनके जाने के बाद कोई विवाद उत्पन्न न हो।

संत के पास कुल सत्रह ऊंट थे। उन्होंने अपनी वसीयत में यह लिखा कि उनके देहांत के बाद सबसे बड़े शिष्य को कुल ऊंटों का आधा हिस्सा दिया जाए, दूसरे शिष्य को एक-तिहाई हिस्सा और सबसे छोटे शिष्य को नौवां हिस्सा दिया जाए। पहली नजर में यह बंटवारा पूरी तरह न्यायसंगत लगता था, लेकिन जब संत का देहांत हुआ और शिष्यों ने इस वसीयत को पढ़ा, तो वे गहरी उलझन में पड़ गए।

समस्या यह थी कि सत्रह ऊंटों का आधा आठ और आधा होता है, जिसे बांटना संभव नहीं था। इसी प्रकार एक-तिहाई और नौवां भाग भी पूर्णांक में नहीं आ रहे थे। अब तीनों शिष्य चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि क्या उनके गुरु से कोई भूल हो गई, या फिर इस वसीयत के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। धीरे-धीरे उनके मन में असमंजस बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने आपसी विवाद से बचते हुए समाधान खोजने का निश्चय किया।

आखिरकार वे सभी महान बुद्धिमान और न्यायप्रिय हजरत अली के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी पूरी समस्या उनके सामने रखी और मार्गदर्शन की प्रार्थना की। हजरत अली ने उनकी बात को ध्यान से सुना और कुछ क्षणों के लिए शांत रहे। फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, मानो वे पहले से ही इस समस्या का हल जानते हों।

उन्होंने कहा कि इस समस्या में कोई जटिलता नहीं है, केवल देखने का नजरिया बदलने की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने एक अनोखा उपाय सुझाया। उन्होंने अपनी ओर से एक ऊंट उन सत्रह ऊंटों में जोड़ दिया। अब कुल ऊंटों की संख्या अठारह हो गई। इसके बाद उन्होंने वसीयत के अनुसार बंटवारा करना शुरू किया।

सबसे बड़े शिष्य को अठारह का आधा यानी नौ ऊंट दिए गए। दूसरे शिष्य को अठारह का एक-तिहाई यानी छह ऊंट मिले। सबसे छोटे शिष्य को अठारह का नौवां हिस्सा यानी दो ऊंट दिए गए। जब इन तीनों हिस्सों को जोड़ा गया, तो कुल संख्या सत्रह ही बनी—नौ, छह और दो मिलाकर सत्रह। इस प्रकार सभी शिष्यों को उनका हिस्सा पूर्ण रूप से मिल गया और किसी भी ऊंट को काटने या विभाजित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके बाद हजरत अली ने अपना एक ऊंट वापस ले लिया।

यह समाधान इतना सरल और अद्भुत था कि तीनों शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें यह समझ में आ गया कि उनके गुरु की वसीयत में कोई त्रुटि नहीं थी, बल्कि वह उनकी समझ और धैर्य की परीक्षा थी। इस पूरी घटना ने उन्हें यह सिखाया कि समस्याओं का समाधान अक्सर हमारे सामने ही होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हमारी सोच सीमित होती है।

यह कथा केवल एक गणितीय चतुराई का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सिद्धांतों को भी उजागर करती है। यह हमें सिखाती है कि जब हम किसी समस्या में फँस जाते हैं, तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। अक्सर हम उसी ढाँचे में सोचते रहते हैं, जिसमें समस्या उत्पन्न हुई होती है, और यही कारण है कि हमें समाधान दिखाई नहीं देता।

इस कहानी में "एक ऊंट" केवल एक अतिरिक्त पशु नहीं है, बल्कि यह प्रतीक है उस अतिरिक्त सोच का, उस नई दृष्टि का, जो हमें समस्याओं से बाहर निकालती है। जीवन में भी कई बार हमें ऐसे ही "एक ऊंट" की आवश्यकता होती है। यह "एक ऊंट" कभी धैर्य के रूप में आता है, कभी किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह के रूप में, तो कभी आत्मचिंतन के रूप में।

यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार को त्यागकर सही मार्गदर्शन लेना कितना आवश्यक है। यदि तीनों शिष्य अपने-अपने तर्कों में उलझे रहते, तो संभव था कि वे आपस में विवाद कर बैठते। लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाई और एक ज्ञानी व्यक्ति के पास जाकर समाधान प्राप्त किया। यही निर्णय उन्हें संघर्ष से बचाकर संतोष की ओर ले गया।

इसके साथ ही यह कहानी यह भी बताती है कि एक सच्चा मार्गदर्शक वही होता है, जो कठिन परिस्थितियों को सरल बना दे और ऐसा समाधान प्रस्तुत करे, जिसमें सभी का हित निहित हो। हजरत अली ने न केवल समस्या का समाधान किया, बल्कि यह भी दिखाया कि बुद्धिमत्ता का सही उपयोग कैसे किया जाता है।

अंततः यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में समस्याएँ आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका समाधान हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि हम धैर्य, समझदारी और सकारात्मक दृष्टि के साथ आगे बढ़ें, तो हर कठिनाई का हल संभव है। यही जीवन की सच्ची कला है—हर उलझन में अवसर देखना और हर समस्या में समाधान खोज लेना।

मजबूत सेना, स्वदेशी हथियार और नई युद्ध तकनीक, यही है मोदी सरकार की जबरदस्त सामरिक रणनीति

साल 2026 में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन, चीन की आक्रामक सैन्य विस्तार नीति, हिंद महासागर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सीमा क्षेत्रों में लगातार तनाव ने भारत को अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए मजबूर किया है। इसी पृष्ठभूमि में मोदी सरकार ने वर्ष 2026 में ऐसी सामरिक रणनीति अपनाई है जिसका मूल उद्देश्य है सैन्य शक्ति का तीव्र आधुनिकीकरण, स्वदेशी रक्षा उत्पादन का विस्फोटक विस्तार, नई युद्ध तकनीकों में निर्णायक बढ़त और वैश्विक रक्षा कूटनीति का विस्तार।

हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की सबसे पहली और सबसे स्पष्ट प्राथमिकता है रक्षा बजट में निरंतर वृद्धि। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 7.85 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है। यह राशि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दो प्रतिशत है और केंद्र सरकार के कुल खर्च का लगभग 14.67 प्रतिशत हिस्सा रक्षा क्षेत्र को जाता है। इस बजट में 2.19 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं ताकि सेना को अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान, आधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बी, ड्रोन और स्मार्ट हथियारों से लैस किया जा सके।

मोदी सरकार की दूसरी निर्णायक रणनीति है सैन्य आधुनिकीकरण को तेज करना। पिछले कुछ वर्षों में यह स्पष्ट हुआ है कि भारत को एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध की संभावना को ध्यान में रखते हुए अपनी सैन्य क्षमता बढ़ानी होगी। इसी रणनीति के तहत भारत ने नौसेना के लिए 26 आधुनिक राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का लगभग 7.4 अरब डॉलर का समझौता किया है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री शक्ति और मजबूत होगी।

इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के लिए नए लड़ाकू स्क्वॉड्रन, आधुनिक मिसाइल प्रणाली और लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले हथियारों पर तेजी से काम चल रहा है। सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम चीन और पाकिस्तान दोनों से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में उठाया गया है। तीसरी बड़ी प्राथमिकता है आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग का निर्माण। वर्ष 2026 के रक्षा बजट में पूंजीगत खरीद का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा घरेलू उद्योगों से खरीद के लिए निर्धारित किया गया है। इसका अर्थ है कि लगभग 1.39 लाख करोड़ रुपये भारतीय कंपनियों और रक्षा निर्माण इकाइयों को मिलेंगे। इससे न केवल सैन्य क्षमता बढ़ेगी बल्कि देश में विशाल रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र भी विकसित होगा।

इसी दिशा में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा एक बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है जहां अब तक 35000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित हो चुका है। इस परियोजना का लक्ष्य भारत को वैश्विक रक्षा उत्पादन केंद्र बनाना है और हजारों उच्च कौशल रोजगार पैदा करना है।

चौथी रणनीतिक प्राथमिकता है नई पीढ़ी के युद्ध क्षेत्रों में प्रवेश। पारंपरिक युद्ध अब अकेला निर्णायक तत्व नहीं रह गया है। ड्रोन, कृत्रिम बुद्धि आधारित युद्ध प्रणाली, डाटा युद्ध और साइबर युद्ध भविष्य की लड़ाइयों का आधार बनते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने ड्रोन बल, सैन्य जियो स्पेशल एजेंसी, डाटा फोर्स और संज्ञानात्मक युद्ध इकाइयों की स्थापना की दीर्घकालिक योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2047 तक भारत पूरी तरह तकनीकी रूप से उन्नत सैन्य शक्ति बन सके।

पांचवीं प्राथमिकता है रक्षा निर्यात का आक्रामक विस्तार। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने हथियार आयातक देश की छवि से बाहर निकलकर रक्षा निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। उदाहरण के तौर पर हाल ही में इंडोनेशिया ने भारत से लगभग 3800 करोड़ रुपये की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का समझौता किया है। यह सौदा केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सामरिक उपस्थिति मजबूत होती है।

छठी रणनीतिक दिशा है भविष्य के युद्ध खतरों के लिए तैयारी। भारत की नई रक्षा दृष्टि में रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु हमलों से निपटने के लिए विशेष सुरक्षा ढांचे का निर्माण भी शामिल है। रक्षा बल विजन 2047 दस्तावेज में स्पष्ट किया गया है कि भविष्य के युद्ध बहुआयामी होंगे और उनके लिए तेज प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करना आवश्यक है।

इन सभी पहलों का व्यापक लक्ष्य है भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित और सैन्य दृष्टि से आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना। देखा जाये तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा प्रस्तुत रक्षा विजन 2047 राष्ट्रीय शक्ति के समग्र विस्तार का खाका है जिसमें सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और तकनीकी नवाचार को एक साथ जोड़ा गया है।

कुल मिलाकर देखें तो वर्ष 2026 में मोदी सरकार की रणनीतिक प्राथमिकताएं बेहद स्पष्ट और आक्रामक हैं। विशाल रक्षा बजट, तेज सैन्य आधुनिकीकरण, स्वदेशी हथियार निर्माण, नई युद्ध तकनीकों में निवेश, रक्षा निर्यात का विस्तार और भविष्य के युद्धों के लिए तैयारी, ये सभी कदम मिलकर भारत को एक उभरती वैश्विक सैन्य शक्ति में बदलने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। यदि यह रणनीति इसी गति से लागू होती रही तो आने वाले दशक में भारत केवल दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था का केंद्र नहीं रहेगा बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की शक्ति संतुलन राजनीति में भी निर्णायक भूमिका निभाएगा।

अभियान

मातृत्व की महिमा और पुत्र का आशीर्वाद: जब भगवान गणेश ने माता पार्वती को दिया दिव्य वरदान

भारतीय पौराणिक परंपरा में मां और पुत्र के संबंध को सबसे पवित्र और भावनात्मक माना गया है, और इस दिव्य संबंध का सर्वोच्च उदाहरण भगवान गणेश और माता पार्वती के बीच देखने को मिलता है। यह केवल एक सामान्य मां-बेटे का संबंध नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, भक्ति और आशीर्वाद का अद्भुत संगम है। इस कथा में वह दिव्य क्षण भी समाहित है जब पुत्र ने अपनी मां को ऐसा वरदान दिया, जिसने मातृत्व के सुख को संपूर्ण संसार में प्रसारित कर दिया।

कथा की शुरुआत उस अद्भुत प्रसंग से होती है जब माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन और दिव्य शक्ति से एक बालक की रचना की। वह बालक कोई और नहीं, बल्कि भगवान गणेश थे। माता ने उन्हें अपने द्वार का रक्षक बनाकर आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही हैं, तब तक कोई भी भीतर प्रवेश न करे। यह आदेश एक साधारण निर्देश नहीं था, बल्कि पुत्र के लिए यह अपनी मां के प्रति पहली सेवा और कर्तव्य की परीक्षा थी।

इसी बीच भगवान शिव वहां पहुंचे और भीतर जाने का प्रयास करने लगे। लेकिन बालक गणेश ने अपनी मां की आज्ञा का

पालन करते हुए उन्हें रोक दिया। इस घटना ने एक बड़ा संघर्ष उत्पन्न किया, जिसमें अंततः गणेश का मस्तक काट दिया गया। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला, तो उनका क्रोध और दुःख इतना प्रबल हुआ कि सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने स्थिति को संभालते हुए गणेश को हाथी का मस्तक लगाकर पुनर्जीवित किया और उन्हें प्रथम पूज्य देवता होने का वरदान दिया।

इस घटना के बाद भगवान गणेश और माता पार्वती के बीच का संबंध और भी गहरा हो गया। यह केवल जन्म का नहीं, बल्कि आत्मा और भावनाओं का संबंध बन गया। माता ने अपने पुत्र को संस्कार, ज्ञान और जीवन की शिक्षाएं दीं, और गणेश ने उन सभी को अपने जीवन में आत्मसात किया।

समय के साथ एक ऐसा प्रसंग आया, जब माता पार्वती ने अपने पुत्र के कल्याण और सुख के लिए एक विशेष व्रत किया। यह व्रत था संकष्टी चतुर्थी, जो आज भी अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। माता पार्वती ने इस व्रत को पूरी निष्ठा और प्रेम से किया, जिसमें उनका संपूर्ण मन अपने पुत्र की रक्षा और सुख-समृद्धि की कामना में लगा हुआ था।

भगवान गणेश अपनी माता की इस अटूट भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि एक मां अपने पुत्र के लिए किस हद तक समर्पित हो सकती है। यह केवल एक व्रत नहीं था, बल्कि मातृत्व के भाव का सर्वोच्च रूप था। इस भाव से अभिभूत होकर गणेश ने अपनी माता को एक अद्भुत और दिव्य वरदान देने का निर्णय लिया।

उन्होंने माता पार्वती से कहा कि जिस प्रकार आपने अपने पुत्र के लिए यह व्रत किया है, उसी प्रकार जो भी नारी इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत सच्चे मन और श्रद्धा से करेगी, उसे आपके समान मातृत्व का सुख प्राप्त होगा। उसकी संतान भी गुणवान, आज्ञाकारी, दीर्घायु, यशस्वी और सुखी होगी, ठीक वैसे ही जैसे मैं हूं।

यह वरदान केवल संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह संतान के जीवन में आने वाले हर संकट को दूर करने का आशीर्वाद भी था। क्योंकि भगवान गणेश स्वयं विघ्नहर्ता हैं, इसलिए उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जो भी माता इस व्रत को करेगी, उसकी संतान के जीवन में आने वाली बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी।

इस प्रकार एक पुत्र ने अपनी मां के प्रेम और समर्पण को पहचानते हुए उसे ऐसा वरदान दिया, जो आने वाली अनगिनत पीढ़ियों की माताओं के लिए आशीर्वाद बन गया। यह घटना केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब भाव शुद्ध होते हैं, तो ईश्वर भी प्रसन्न होकर वरदान देने को बाध्य हो जाते हैं।

इस कथा का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। माता पार्वती शक्ति का प्रतीक हैं और भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं। जब शक्ति और बुद्धि का संगम होता है, तभी जीवन में संतुलन और समृद्धि आती है। इस कथा में यही संदेश छिपा है कि मातृत्व केवल जन्म देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी ऊर्जा है, जो संपूर्ण सृष्टि को पोषित करती है। आज भी भारत के विभिन्न भागों में माताएं संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती हैं। वे दिनभर उपवास रखकर सायंकाल चंद्रमा के दर्शन के बाद पूजा करती हैं और अपने बच्चों की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और रक्षा की कामना करती हैं। यह परंपरा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह उस दिव्य वरदान की स्मृति है, जो एक पुत्र ने अपनी मां को दिया था।

यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि माता-पिता और संतान के बीच का संबंध केवल कर्तव्यों का नहीं, बल्कि भावनाओं और आशीर्वाद का होता है। जहां माता अपने बच्चे के लिए हर त्याग करने को तैयार रहती है, वहीं संतान भी अपने प्रेम और सम्मान से माता-पिता को गौरवान्वित करती है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि भगवान गणेश और माता पार्वती की यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण ही वह शक्ति है, जो साधारण को असाधारण बना देती है। मातृत्व का यह आशीर्वाद और पुत्र का यह वरदान आज भी हर उस हृदय में जीवित है, जहां प्रेम और विश्वास की ज्योति प्रज्वलित है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

ऐतिहासिक बंदरगाह से औद्योगिक शक्ति तक, सूरत की विकास यात्रा ने रचे कई नए

- सूरत दुनिया के लगभग 90% प्राकृतिक हीरों और 25% लैब-निर्मित हीरों की प्रोसेसिंग करता है।
- करीब 6,000 डायमंड यूनिट्स, जिनमें 70% MSMEs रोजगार और निर्यात का बड़ा आधार
- 16वीं सदी का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह आज आधुनिक औद्योगिक और टेक्सटाइल हब में तब्दील।
- Growth Hub पहल के तहत सूरत को इंटीग्रेटेड रीजनल डेवलपमेंट के पायलट के रूप में चुना गया।
- सूरत आर्थिक क्षेत्र (SER) मास्टर प्लान के जरिए पूरे दक्षिण गुजरात को ग्लोबल इकोनॉमिक हब बनाने का लक्ष्य।

(जीएनएस)। गांधीनगर : सूरत, गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर और भारत का नौवां सबसे बड़ा शहर,

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के कुशल नेतृत्व में एक वैश्विक औद्योगिक शक्ति के रूप में विकसित हुआ है। सूरत तापी नदी के किनारे स्थित यह शहर हीरा और रेशम उद्योग में अपनी उत्कृष्टता के कारण 'डायमंड सिटी' और 'सिल्क सिटी' जैसे उपनामों से प्रसिद्ध है। भारत के सबसे प्रगतिशील और उद्यमशील शहरों में से एक, सूरत गर्व से गुजरात की समृद्ध विरासत और दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। इस शहर ने निरंतर अवसरों को उपलब्धियों में बदलते हुए मजबूत बुनियादी ढांचा, कुशल नागरिक सेवाएं और एक गतिशील औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है। अपनी रणनीतिक तटीय स्थिति के कारण, सूरत भारत का एक महत्वपूर्ण पश्चिमी प्रवेश द्वार बन गया। 16वीं शताब्दी में यह भारत और कई पश्चिमी देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण

व्यापारिक कड़ी के रूप में उभरा।

सूरत बंदरगाह के रणनीतिक महत्व के कारण ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच शक्तियों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और सहभागिता बढ़ी, जिससे शहर का व्यापारिक नेटवर्क विस्तृत हुआ। उसी समय, यह शहर जहाज निर्माण का एक प्रमुख केंद्र भी था। इस प्रकार, यह अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्रों में से एक बन गया। आज सूरत हीरा के आभूषण बनाने और पॉलिशिंग

का अग्रणी केंद्र है, साथ ही एशिया के सबसे बड़े वस्त्र केंद्रों में से भी एक है, जो वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता प्रदान करने में सटीकता, रचनात्मकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।

सूरत विश्व के लगभग 90% प्राकृतिक हीरों और लगभग 25% लैब-निर्मित हीरों का प्रसंस्करण करता है। यहां लगभग 6,000 हीरा काटने और पॉलिशिंग इकाइयां हैं, जिनमें से लगभग 70% सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) हैं। शहर का मजबूत MSME क्षेत्र, कुशल कार्यबल और व्यापार-अनुकूल वातावरण इसे गुजरात की आर्थिक शक्ति का प्रमुख योगदानकर्ता बनाते हैं। आधुनिक शहरी नियोजन, बेहतर कनेक्टिविटी और सतत विकास पहलों ने सूरत को भारत के सबसे तेजी से विकसित और रहने योग्य शहरों में शामिल किया है। आगामी वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन (VGRC) के आयोजन के साथ सूरत एक बार फिर अपनी प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रहा है। विरासत में जड़ें और महत्वाकांक्षा से प्रेरित यह शहर साझेदारी और समृद्धि के नए अवसर खोलता जा रहा है। अपने अटूट संकल्प और वैश्विक दृष्टिकोण के साथ, सूरत गुजरात और देश के विकास के अगले दौर का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। नीति आयोग की ग्रोथ हब (G Hub) पहल के तहत, सूरत को प्रमुख शहर क्षेत्रों में से एक के रूप में चुना गया है, जहां एकीकृत क्षेत्रीय विकास के नए मॉडल का पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना और परस्पर जुड़े जिलों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए एक व्यापक ढांचा और दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना है। इस दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए, नीति आयोग के सूरत आर्थिक क्षेत्र (SER) आर्थिक मास्टर प्लान ने दक्षिण गुजरात क्षेत्र जिसमें सूरत, भरूच, नवसारी, तापी, डांग और वलसाड शामिल हैं को 2047 तक एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी आर्थिक केंद्र में परिवर्तित करने का महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है।

गिरनार अंबाजी मंदिर में पवित्रता से खिलवाड़ पर बड़ा एक्शन, 11 पुजारियों पर केस के आदेश से मचा हड़कंप

(जीएनएस)। गुजरात के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल गिरनार अंबाजी मंदिर से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। मंदिर परिसर में कथित रूप से शराब और मांसाहार के साथ पार्टी किए जाने और दान राशि में गड़बड़ी के आरोपों ने न केवल स्थानीय प्रशासन को सक्रिय कर दिया, बल्कि पूरे राज्य में आस्था और व्यवस्था को लेकर गहन चर्चा भी छेड़ दी है। इस मामले में कुल 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे मंदिर प्रबंधन और जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है।

घटनाक्रम की शुरुआत एक वायरल वीडियो से हुई, जिसने पूरे मामले को उजागर किया। वीडियो में कथित तौर पर मंदिर परिसर के भीतर कुछ लोग शराब और मांसाहार का सेवन करते हुए नजर आए। जैसे ही यह वीडियो सामने आया, लोगों में आक्रोश फैल गया और प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जूनागढ़ के कलेक्टर अनिल रणवासिया ने तत्काल संज्ञान लेते हुए विस्तृत जांच के आदेश जारी किए।

जांच में जो तथ्य सामने आए, वे और भी अधिक चिंताजनक थे। रिपोर्ट के अनुसार, 22 अक्टूबर को कुछ लोग मंदिर की सीढ़ियों के रास्ते शराब और

मांसाहार सामग्री लेकर अंदर पहुंचे और चार दिनों तक वहीं ठहरकर पार्टी करते रहे। यह तथ्य न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है, बल्कि मंदिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। इस मामले में दो नाबालिगों सहित कुल छह व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इनमें अभिषेक चौहान, छगन डाभी, निखिल मेघनाथी और जिग्नेश डाभी जैसे नाम शामिल हैं।

मामले का दूसरा और शायद अधिक गंभीर पहलू वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। जांच के दौरान यह आरोप सामने आया कि मंदिर में आने वाली दान राशि में गड़बड़ी की गई और लाखों रुपये के गबन की आशंका है। इस आरोप ने पूरे मामले को केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक बड़े आर्थिक अपराध की दिशा में भी मोड़ दिया। इस संबंध में पांच पुजारियों—योगेशगिरि, दुष्यंतगिरि, कुंदनगिरि, देवगिरि और भरतनाथ—के खिलाफ दूसरी शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने इस पूरे घटनाक्रम को अत्यंत गंभीर मानते हुए त्वरित कार्रवाई की। कलेक्टर अनिल रणवासिया ने आरोपियों को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटाने के निर्देश दिए। इसके तहत कुल 11 लोगों—जिनमें पुजारी और सहायक कर्मचारी शामिल हैं—को उनके कार्य से अलग कर दिया गया है। साथ ही मंदिर की दैनिक पूजा और व्यवस्थाओं को प्रभावित न होने देने के लिए तीन नए पुजारियों की अस्थायी नियुक्ति की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

इस पूरे मामले ने मंदिर प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यही कारण है कि जांच को केवल आरोपियों तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। मंदिर के प्रशासक और नगर पालिका के मामलतदार को नोटिस जारी किए गए हैं। स्पष्ट किया गया है कि यदि जांच में उनकी लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि यह समाज की आस्था और विश्वास से भी गहराई से जुड़ी हुई है। मंदिर जैसे पवित्र स्थल, जहां लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं, वहां इस प्रकार की गतिविधियों का होना लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला है। यही कारण है कि स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच इस घटना को लेकर गहरा रोष है। उनका मानना है कि मंदिर केवल एक इमारत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र है, जिसकी पवित्रता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।

विशेषज्ञों का भी मानना है कि इस घटना ने धार्मिक स्थलों के प्रबंधन और पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर किया है। बड़े मंदिरों में दान की भारी राशि आती है, जिसके उचित प्रबंधन और निगरानी के लिए मजबूत प्रणाली होना बेहद जरूरी है। यदि समय-समय पर ऑडिट और निरीक्षण न किया जाए, तो इस प्रकार की अनियमितताओं के पनपने की संभावना बढ़ जाती है।

प्रशासन की सख्त कार्रवाई ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि चाहे मामला कितना भी संवेदनशील क्यों न हो, कानून के सामने सभी समान हैं। धार्मिक आस्था के नाम पर किसी भी प्रकार की अनियमितता या अनुचित गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अब इस मामले में आगे की जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्या और नए तथ्य सामने आते हैं और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। साथ ही, यह भी अपेक्षा की जा रही है कि इस घटना के बाद मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

यह पूरा घटनाक्रम एक चेतावनी की तरह है—न केवल प्रशासन के लिए, बल्कि समाज के लिए भी—कि आस्था के केंद्रों की पवित्रता और विश्वास को बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है, और इसमें किसी भी प्रकार की चूक के लिए सख्त जवाबदेही तय होना अनिवार्य है।

रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में विभिन्न रेल परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी

मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल एवं विभिन्न रेल परियोजनाओं का तेजी से कार्य प्रगति पर

मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल: वायाडक्ट, पियर और ट्रैक बिछाने का काम तेजी से जारी

सीमा क्षेत्रों में कनेक्टिविटी: देशलपार-हाजीपीर और वायोर-लखपत जैसे मार्गों पर सर्वेक्षण

(जीएनएस)। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में भारतीय रेलवे की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि देशभर में रेल अवसंरचना के विकास को अभूतपूर्व गति दी जा रही है।

रेल मंत्री ने गुजरात से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) परियोजना पर तेजी से कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के अंतर्गत 300 किलोमीटर से अधिक वायाडक्ट का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जबकि पियर निर्माण, ट्रैक बिछाने तथा स्टेशनों के विकास का कार्य निरंतर जारी है। इसके साथ ही भारत की पहली अंडर सी रेल सुरंग पर भी कार्य प्रगति पर है।

उन्होंने बताया कि परियोजना के अंतर्गत 435 किलोमीटर फाउंडेशन कार्य, 338 किलोमीटर गर्डर इंस्टॉलेशन तथा 168 किलोमीटर ट्रैक बिछाने के साथ ओएचई इंस्टॉलेशन का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वापी, बिलिमोरा, सूरत तथा बीकेसी सहित कई स्टेशनों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

रेल मंत्री ने जानकारी दी कि कई नदियों पर पुलों का निर्माण पूरा किया जा चुका है तथा भरूच, वडोदरा, आनंद, नडियाद, अहमदाबाद एवं साबरमती क्षेत्रों में कार्य तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।

सीमा क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए रेलवे लाइनों के सर्वेक्षण भी किए जा रहे हैं। कच्छ क्षेत्र में देशलपार–हाजीपीर तथा वायोर–लखपत के बीच नई रेल कनेक्टिविटी विकसित करने की योजना पर कार्य प्रारंभ किया गया है।

भारतीय रेलवे वर्तमान में अभूतपूर्व विस्तार और आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है, जिसे केंद्रीय बजट 2026-27 में 2.78 लाख करोड़ के रिकॉर्ड बजटीय आवंटन

से सशक्त बनाया गया है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 5 लाख रोजगार सृजित हुए हैं, जबकि बीते 2 वर्षों में 1.43 लाख सीधी नियुक्तियां की गई हैं।

सुरक्षा अवसंरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए आरओबी और आरयूबी की संख्या लगभग 4,000 से बढ़कर 14,000 हो गई है। ऑटोमैटिक सिग्नलिंग का विस्तार भी 1,500 किलोमीटर से बढ़कर 4,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। सुरक्षा तकनीक पर चर्चा करते हुए, उन्होंने स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली 'कवच' की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि लगभग 3,000 किलोमीटर के नेटवर्क को पहले ही इसके दायरे में लाया जा चुका है, जबकि करीब 20,000 किलोमीटर पर कार्य प्रगति पर है और लगभग 8,000 रेल इंजनों में इसे लगाने की योजना है।

रेल मंत्री ने बताया कि एलएचबी कोचों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और हाल के वर्षों में लगभग 48,000 कोच जोड़े गए हैं। लोकोमोटिव उत्पादन लगभग 12,000 यूनिट तक पहुंच गया है तथा वैगनों की संख्या 2 लाख से अधिक हो गई है।

टनल निर्माण के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। वर्ष 2014 तक जहां लगभग 125 किलोमीटर टनल का निर्माण हुआ था, वहीं उसके बाद 486 किलोमीटर अतिरिक्त टनल बनाई गई हैं, जिससे पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर जैसे दुर्गम क्षेत्रों में संपर्क में सुधार हुआ है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) के निर्माण में भी व्यापक प्रगति हुई है। लगभग 2,800 किलोमीटर कॉरिडोर का कार्य पूरा हो चुका है, जिन पर प्रतिदिन लगभग 480 मालगाड़ियां संचालित हो रही हैं।

यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जनरल कोचों की शुरुआत की गई है, जिनमें वर्ष 2024-25 में लगभग 1,250 और 2025-26 में करीब 860 कोच शामिल हैं।

रेल मंत्री ने बताया कि वर्तमान में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेन सेवाएं संचालित हैं तथा 60 अमृत भारत ट्रेनें किफायती लंबी दूरी की यात्रा सुविधा प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त 133 अमृत भारत ट्रेनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।

उन्होंने बताया कि 75 प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया विकसित किए जा रहे हैं तथा यात्रियों की सुविधा के लिए 1,200 से अधिक नई ईएमयू/मेमू सेवाएं शुरू की गई हैं।

रेल मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि भारतीय रेलवे ने विश्व के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक शुरू किया है, जिसके अंतर्गत लगभग 1,300 स्टेशनों को शामिल किया गया है। इनमें से करीब 180 स्टेशनों का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि लगभग 500 स्टेशन उन्नत चरण में हैं।

AI की नई उड़ान: वडोदरा में 'अदिति AI लैब' से तैयार होगी भविष्य की टेक पीढ़ी

(जीएनएस)। वडोदरा में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अग्रणी टेक कंसल्टिंग कंपनी Aditi Consulting ने 'अदिति AI लैब' का भव्य शुभारंभ किया है। यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक तेजी से हर क्षेत्र को बदल रही है और कुशल AI इंजीनियरों की मांग अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुकी है। इस नई लैब का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि भारत के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और सक्षम टेक प्रोफेशनल्स के रूप में तैयार करना है।

लॉन्च कार्यक्रम में उद्योग जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति ने इस पहल के महत्व को और भी रेखांकित किया। हिमांशु पटेल, गौरांग पी. जोशीपुरा और मयंक आर. ब्रह्मभट्ट जैसे अनुभवी उद्योग विशेषज्ञों ने AI, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल नवाचार के बढ़ते प्रभाव पर अपने विचार साझा किए। सभी वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले समय में वही देश और समाज आगे बढ़ेंगे, जो तकनीक और नवाचार को अपनाने में सबसे आगे होंगे। 'अदिति AI लैब' की सबसे बड़ी विशेषता इसका 12 महीने

का संरचित अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, जिसे खास तौर पर इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रोग्राम पारंपरिक थ्योरी-आधारित शिक्षा से अलग हटकर पूरी तरह प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री-ओरिएंटेड है। इसमें प्रतिभागियों को केवल AI के सिद्धांत नहीं सिखाए जाएंगे, बल्कि उन्हें वास्तविक समस्याओं पर काम करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान वे डेटा इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट, और AI सिस्टम्स के डिप्लॉयमेंट जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण स्किल्स में दक्षता हासिल करेंगे।

इस लैब का दृष्टिकोण केवल तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं को एक संपूर्ण पेशेवर के रूप में विकसित करने पर केंद्रित है। प्रतिभागियों को टेलीकॉम, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग जैसे विविध क्षेत्रों के प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा, जिससे वे अलग-अलग इंडस्ट्री की जरूरतों और चुनौतियों को समझ सकेंगे। इससे उनके भीतर समस्या समाधान की क्षमता विकसित होगी, जो किसी भी सफल AI इंजीनियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। रमना वडावल्ली ने इस अवसर पर कहा कि आज एंटरप्राइज AI के युग में तकनीक केवल एक उपकरण नहीं रह गई है, बल्कि यह व्यवसायों के संचालन का मूल आधार बन चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि AI का वास्तविक प्रभाव उन इंजीनियरों पर निर्भर करता है, जो इन जटिल सिस्टम्स को डिजाइन और लागू करते हैं। इसलिए इस तरह की पहलें न केवल उद्योग की जरूरतों को पूरा करती हैं, बल्कि देश के तकनीकी भविष्य को भी मजबूत बनाती हैं। वहीं मानस महाराणा ने बताया कि इस AI लैब को एंटरप्राइज-ग्रेड वातावरण के रूप में तैयार किया गया है। इसका मतलब है कि यहां छात्रों को वही टूल्स, तकनीक और कार्यप्रणाली सिखाई जाएगी, जो बड़े कॉर्पोरेट संगठनों में इस्तेमाल होती है। इससे प्रशिक्षण के दौरान ही उन्हें वास्तविक कार्य अनुभव मिलेगा, जिससे वे नौकरी के लिए पूरी तरह तैयार हो सकेंगे। भारत जैसे देश के लिए, जहां हर साल लाखों इंजीनियरिंग छात्र स्नातक होते हैं, इस तरह की पहल बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा गया है कि डिग्री होने के बावजूद छात्रों में इंडस्ट्री के अनुरूप कौशल की कमी रह जाती है। 'अदिति AI लैब' इस अंतर को भरने का प्रयास कर रही है, जिससे 'स्किल गैप' को कम किया जा सके और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

गुजरात, जो पहले से ही औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता है, अब तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। वडोदरा में इस लैब की स्थापना से न केवल स्थानीय युवाओं को लाभ मिलेगा, बल्कि यह पूरे राज्य के लिए एक टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित होने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में AI का प्रभाव स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, परिवहन और विनिर्माण जैसे लगभग हर क्षेत्र में दिखाई देगा। ऐसे में कुशल AI इंजीनियरों की मांग लगातार बढ़ेगी। 'अदिति AI लैब' जैसी पहलें इस मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं और भारत को वैश्विक AI हब बनने की दिशा में आगे बढ़ा सकती हैं।

इस पहल के साथ एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं रहना चाहता, बल्कि वह इसके निर्माण और विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वडोदरा में शुरू हुई यह लैब उसी परिवर्तन की एक मजबूत कड़ी है, जो आने वाले समय में देश के तकनीकी परिदृश्य को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।

पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन द्वारा पश्चिम रेलवे की महिला कर्मचारियों का सम्मान

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO) द्वारा पश्चिम रेलवे की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत उत्कृष्ट महिला कर्मचारियों को उनके समर्पण, प्रतिबद्धता एवं अपने-अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित करने हेतु एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह कार्यक्रम 16 मार्च, 2026 को सौहार्दपूर्ण एवं उत्सवपूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया, जिसमें महिला रेल कर्मचारी एवं पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन के सदस्य उपस्थित थीं। पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती ईशा मलिक ने विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाली 57 महिला कर्मचारियों को कार्यकारी समिति के सदस्यों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रशस्ति पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।

इस कार्यक्रम में महिला कर्मचारियों

के संगठन के सुचारु संचालन में उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित किया गया तथा उच्चस्तर की व्यावसायिकता बनाए रखने में उनके निरंतर प्रयासों की सराहना की गई। यह सम्मान समारोह उनके समर्पण, निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक रहा।

सभा को संबोधित करते हुए श्रीमती मलिक ने संगठन में महिला कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की तथा उनकी इस क्षमता की प्रशंसा की कि वे अपने व्यावसायिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए कार्य एवं निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखती हैं। उन्होंने पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को कार्यस्थल से आगे बढ़कर बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित किया। समान अवसरों के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग दिया जाना चाहिए तथा उन्हें आत्मविश्वासी, स्वतंत्र एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए।

यह कार्यक्रम न केवल महिला कर्मचारियों की उपलब्धियों का उत्सव था, बल्कि सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए समावेशी, सहयोगपूर्ण एवं सशक्त कार्य वातावरण निर्माण के प्रति पश्चिम रेलवे की प्रतिबद्धता को भी पुनः रेखांकित करता है।

स्वच्छता के सिपाहियों का सम्मान: जसदण में सफाई कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की अनोखी पहल

(जीएनएस)। राजकोट जिले के जसदण शहर में स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एक सराहनीय पहल सामने आई है। जसदण नगर पालिका द्वारा आयोजित विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर ने यह साबित कर दिया कि शहर को साफ रखने वाले इन 'स्वच्छता सैनिकों' की सेहत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी शहर की सफाई। यह आयोजन केवल एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि उन कर्मचारियों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक था, जो प्रतिदिन कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए समाज को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखते हैं। इस विशेष हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन तालुका हेल्थ ऑफिस में किया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने बड़ी संख्या में उपस्थित सफाई कर्मचारियों का विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और श्वसन संबंधी बीमारियों की जांच को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि यह समस्याएं ऐसे कर्मचारियों में सामान्य रूप से पाई जाती हैं, जो रोजाना धूल, कचरे और प्रदूषण के संपर्क में रहते हैं। शिविर में कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थिति का बारीकी से मूल्यांकन किया गया, ताकि संभावित बीमारियों की समय रहते पहचान हो सके और उनका उचित इलाज सुनिश्चित किया जा सके। यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सफाई कर्मचारी अक्सर अपने काम की प्रकृति के कारण कई प्रकार के स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करते हैं। कचरे के ढेर, सीवर लाइनों और प्रदूषित वातावरण में काम करने के चलते उन्हें संक्रमण, सांस संबंधी समस्याएं और त्वचा रोगों का खतरा बना रहता है। ऐसे में नियमित स्वास्थ्य जांच न केवल उनकी कार्यक्षमता को बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाती है। शिविर के दौरान डॉक्टरों ने केवल जांच ही नहीं की, बल्कि कर्मचारियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। उन्हें संतुलित आहार लेने, नियमित व्यायाम करने और कार्य के दौरान सुरक्षा उपायों का पालन करने के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही यह भी समझाया गया कि यदि किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या के लक्षण दिखाई दें, तो उसे नजरअंदाज न करें और तुरंत चिकित्सा परामर्श लें। नगर पालिका के इस प्रयास को स्थानीय स्तर पर व्यापक सराहना मिली है। यह पहल एक सकारात्मक संदेश देती है कि समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से उन लोगों का ध्यान रखना जरूरी है, जो परोक्ष रूप से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। अक्सर सफाई कर्मचारियों के योगदान को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इस तरह के आयोजन उनके महत्व को पहचानने और उन्हें सम्मान देने का कार्य करते हैं। इस कार्यक्रम ने यह भी संकेत दिया कि स्थानीय प्रशासन अब केवल बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह मानव संसाधन के कल्याण को भी प्राथमिकता दे रहा है।

ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु अहमदाबाद मंडल में आधुनिक रसोई उपकरणों की आपूर्ति

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने एवं गैस पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से मंडल के विभिन्न रनिंग रूमों एवं प्रशिक्षण केंद्रों में आधुनिक विद्युत-आधारित रसोई उपकरणों की आपूर्ति का कार्य निरंतर प्रगति पर है। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि कार्यस्थलों पर सुरक्षित एवं सुविधाजनक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की दिशा में भी प्रभावी सिद्ध हो रही है।

इसी परिप्रेक्ष्य में, आज भुज एवं सनोसरा स्थित रनिंग रूमों सहित प्रशिक्षण केंद्रों को सुदृढ़ एवं उन्नत रसोई सुविधाओं से सुसज्जित करने के उद्देश्य से ओवन, कुकर, इंडक्शन कुकटॉप, रोटी तवा, ग्लास मिक्सिंग बाउल तथा पतीलों की आपूर्ति की गई। इससे संबंधित इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं ऊर्जा-कुशल खानपान सुविधाएं उपलब्ध होंगी, साथ ही भोजन तैयारी की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक, त्वरित एवं आधुनिक बनेगी।

अहमदाबाद मंडल द्वारा इसी प्रकार मंडल के अन्य प्रमुख रनिंग रूमों जैसे अहमदाबाद, साबरमती, गांधीधाम, विरमगाम सहित प्रशिक्षण केंद्रों में भी चरणबद्ध तरीके से इन आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, जिससे ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल कार्य प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का एआई सेक्टर के युवा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए अनूठा दृष्टिकोण

- मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों के उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप्स के साथ प्रत्यक्ष संवाद किया
- मुख्यमंत्री निवास परिसर में युवा स्टार्टअप के प्रोडक्ट की प्रदर्शनी देखी
- गुजरात को एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए ग्लोबल सेंटर बनाने की दिशा में राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का बहुआयामी आयोजन
- गुजरात एआई टेक्नोलॉजी के कार्यान्वयन में देश का अग्रणी राज्य बनेगा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
- मुख्यमंत्री ने शासन में पारदर्शिता और नागरिकों की खुशहाली के लिए एआई टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग करने की गुजरात सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की
- युवा स्टार्टअप्स ने गुजरात सरकार की युवा प्रोत्साहक कार्यपद्धति की खुले मन से प्रशंसा की
- राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने दो महत्वपूर्ण एएमयू पर हस्ताक्षर किए
- सर्वम एआई गुजरात में एक आधुनिक सॉवरेन एआई पार्क स्थापित करेगा
- स्टार्टअप को एआई सॉल्यूशन के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए राज्य सरकार द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट मॉडल की घोषणा

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में बुधवार को गांधीनगर में स्टार्टअप संवाद का महत्वपूर्ण आयोजन किया गया। यह संवाद गुजरात को युवा स्टार्टअप्स के स्केलेबल और इफेक्टिव सॉल्यूशंस के जरिए और अधिक सक्षम बनाकर एआई और उभरती टेक्नोलॉजी (इमर्जिंग टेक्नोलॉजी) के लिए ग्लोबल सेंटर बनाने की दिशा में सार्थक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने इस स्टार्टअप संवाद में देश के विभिन्न राज्यों के 24 उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप्स के साथ प्रत्यक्ष संवाद-बातचीत की और उनके अनुभवों एवं नवाचारों (इनोवेशन) के बारे में जानने की काफी उत्सुकता दिखाई। स्टार्टअप्स के साथ इस संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य के विकास की जो मजबूत नींव रखी थी, उसके चलते आज गुजरात वित्तीय अनुशासन के साथ नई टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाने में देश में शीर्ष स्थान पर है। इतना ही नहीं, राज्य एआई, सेमीकंडक्टर और ग्रीन ग्रोथ जैसे इमर्जिंग सेक्टर के जरिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस संवाद के दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई टेक्नोलॉजी के विभिन्न उपयोग से संबंधित 5 स्टार्टअप, हेल्थ सेक्टर में 3 और शिक्षा के विभिन्न आयामों पर एआई आधारित कार्य करने वाले 6 तथा सरकारी और उद्योग क्षेत्र के 10 स्टार्टअप ने मुख्यमंत्री और अन्य महानुभावों के समक्ष अपने कामकाज और प्रोडक्ट पर प्रेजेंटेशन दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सरकार की मंशा ऐसे प्रतिभाशाली स्टार्टअप्स को प्राथमिकता देने की है, जो सरकार के साथ काम करने को उत्सुक हैं, ताकि नवाचार और नए उद्यमियों को बढ़ावा मिले। उन्होंने यह भी कहा कि एआई के उपयोग से सरकारी कामकाज की गति को और बढ़ाना, कार्य में और पारदर्शिता लाना और सरकारी योजनाओं का लाभ

टेक्नोलॉजी के जरिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, यही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की खुशहाली और सरकार की कार्यदक्षता बढ़ाने वाले प्रत्येक स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए तत्पर है, लेकिन इस विजन को साकार करने के लिए सभी का प्रयास और दिशा एक होनी बहुत ही जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टेक्नोलॉजी-आधारित विकास में 'क्वालिटी' राज्य सरकार की प्रथम प्राथमिकता रहेगी। राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से मुख्यमंत्री आवास में आयोजित इस एआई संवाद के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और सर्वम एआई तथा माइको (MIKO) स्टार्टअप के बीच हुए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, गुजरात की पेमेंट मोडालिटीज (भुगतान के तरीके या माध्यम) का भी लोकार्पण किया गया।

इस एमओयू के अंतर्गत सर्वम एआई द्वारा गुजरात में एक आधुनिक संप्रभु (सॉवरेन) एआई पार्क स्थापित किया जाएगा। इस एआई पार्क में एआई के लिए आवश्यक हाई-एंड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और इनोवेशन के लिए सेंटर्स, युवाओं के लिए कौशल विकास, सरकार के लिए एआई-आधारित सॉल्यूशंस, नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी जैसी सारी सुविधाएं एक ही परिसर में विकसित की जाएंगी। राज्य सरकार और सर्वम एआई के बीच हुए इस एमओयू के परिणामस्वरूप अगले 5 वर्षों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा एआई और नई टेक्नोलॉजी का एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ा होगा। इसके अलावा, स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और सरकारी सेवाएं और भी स्मार्ट एवं तेज होंगी। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार तेजी से आवश्यक अनुमतियां और क्लीयरेंस देगी। साथ ही, राज्य की नीतियों के अनुसार सहायता और सपोर्ट देगी तथा संबंधित विभागों के साथ तालमेल स्थापित कर प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने में मदद करेगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने एआई इनोवेशन चैलेंज के तहत स्टार्टअप्स को नए एआई सॉल्यूशंस विकसित करने और उन्हें तेजी से क्रियान्वित करने के लिए स्पष्ट एवं पारदर्शी फाइनेंशियल सपोर्ट मॉडल घोषित किया है। इस पहल से स्टार्टअप्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) विकास से लेकर प्रोडक्शन रोलआउट तक के सभी चरणों में मजबूत आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे राज्य में हाई-इम्पेक्ट एआई-आधारित समाधानों को तेजी से लागू किया जा सकेगा। इस पहल के अंतर्गत पीओसी चरण के लिए स्टार्टअप्स को यूज केस के अनुसार सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मॉडरेट यूज केस के लिए 75 लाख रुपए तक और कॉम्प्लेक्स यूज केस के लिए 10 लाख रुपए तक की फंडिंग स्टेप-बाइ-स्टेप दी जाएगी। इस स्कीम के तहत स्टार्टअप का चयन होने के बाद 25 फीसदी राशि तुरंत दी जाएगी, जबकि सफल पीओसी पूरा होने के बाद बाकी की 75 फीसदी राशि दी जाएगी।

पीओसी सफल होने के बाद चुने हुए प्रोजेक्ट्स को फुल-स्केल डिप्लॉयमेंट के लिए अधिक सपोर्ट-सहायता मिलेगी। मॉडरेट प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख रुपए तक और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए 1 करोड़ रुपए तक की सहायता फुल-स्केल डिप्लॉयमेंट, इंप्लिमेंटेशन, कस्टमाइजेशन, फीचर एन्हांसमेंट तथा हैंडहोल्डिंग सपोर्ट के लिए दी जाएगी। इसके अलावा, स्टार्टअप्स को 4 वर्षों तक सपोर्ट मिलेगा, जिसके तहत गुजरात स्टेट डेटा सेंटर और एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाया जा सकता है। इस फाइनेंशियल सपोर्ट मॉडल से स्टार्टअप्स को गुजरात सरकार के साथ सीधे काम करने का अवसर मिलेगा। राज्य को भी हाई-इम्पेक्ट एआई सॉल्यूशंस के तेजी से क्रियान्वयन, सरकारी सेवाओं में अधिक कार्यक्षमता और पारदर्शिता, मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम और गुजरात को एआई इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करने जैसे लाभ प्राप्त होंगे। यह पहल राज्य के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और नागरिक-केंद्रित गवर्नेंस को एक नई ऊंचाई देगी। मुख्यमंत्री ने युवा स्टार्टअप को प्रोत्साहन देते हुए कहा कि इस संवाद से राज्य की विकास प्राथमिकताओं और सुशासन की जरूरतों को समझने के साथ-साथ उसके अनुरूप नवीन टेक्नोलॉजी से स्टार्टअप सपोर्ट के लिए देश भर के ऐसे स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का उद्देश्य पूरा होगा।

इतना ही नहीं, यह संवाद एआई, ड्रोन, हेल्थ एग्रीकल्चर, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी में उभरते अवसरों के मूल्यांकन के जरिए राज्य सरकार के विभागों में कार्यदक्षता, पारदर्शिता और नागरिक सेवाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने में उपयुक्त साबित होगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में इनोवेशन-लेड ग्रोथ के विजन के साथ गुजरात को नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के व्यापक कार्यान्वयन और परिणाम आधारित पद्धति के लिए तैयार करने की नई दिशा इस स्टार्टअप संवाद से खुली है।

इस अवसर पर उद्योग विभाग की अपर मुख्य सचिव सुश्री ममता वर्मा, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मुकेश कुमार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव श्रीमती पी. भारती ने गुजरात के स्टार्टअप इकोसिस्टम और विद्यार्थियों से लेकर स्टार्टअप्स तक, सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता एवं फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, अपर मुख्य सचिव श्री आर.सी. मीणा, श्री राजीव टोपनो, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अजय कुमार, मुख्यमंत्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ओएसडी) श्री अतुल गोर और निदेशक (आईटी और ई-गवर्नेंस) सुश्री कविता शाह सहित विभिन्न क्षेत्रों के युवा स्टार्टअप्स मौजूद रहे।

भावनगर मंडल से होकर चलने वाली कुछ ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

(जीएनएस)। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल अंतर्गत कनकपुरा यार्ड में प्रस्तावित नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण भावनगर मंडल से होकर चलने वाली कुछ ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से प्रभावित रहेगा। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि कनकपुरा यार्ड में रेल लाइनों के मध्य अतिरिक्त कनेक्शन स्थापित किए जाएंगे तथा दो लाइनों का लगभग 100 मीटर तक विस्तार किया जाएगा। इस कार्य से यार्ड की संचालन क्षमता एवं ट्रेनों की आवागमन सुगमता में सुधार होगा।

प्रभावित ट्रेनें निम्नानुसार हैं:

दिनांक 08 मई 2026 को पोरबंदर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 19269 पोरबंदर–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस आंशिक रूप से परिवर्तित मार्ग वाया फुलेरा–रिंगस–रेवाड़ी होकर संचालित होगी। यह ट्रेन जयपुर, अलवर एवं बांदीकुई स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

दिनांक 09 मई 2026 को पोरबंदर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 20937 पोरबंदर–दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस आंशिक रूप से परिवर्तित मार्ग वाया फुलेरा–रिंगस–रेवाड़ी होकर संचालित होगी। यह ट्रेन जयपुर, दौसा, बांदीकुई, अलवर एवं खैरथल स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

दिनांक 11 मई 2026 को मुजफ्फरपुर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 19270 मुजफ्फरपुर–पोरबंदर एक्सप्रेस आंशिक रूप से परिवर्तित मार्ग वाया रेवाड़ी–रिंगस–फुलेरा होकर संचालित होगी। यह ट्रेन अलवर, बांदीकुई एवं जयपुर स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व ट्रेन की अद्यतन जानकारी भारतीय रेल की अधिकृत वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in, एनटीईएस (NTES) अथवा रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 से अवश्य प्राप्त कर लें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने गांधीनगर में सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 182 नई बसों का लोकार्पण किया

- गुजरात एसटी की जनसेवा प्रतिबद्धता का एक और नया माइलस्टोन
- मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायकों एवं पदाधिकारियों की प्रेरक उपस्थिति
- गुजरात एसटी निगम प्रतिदिन 8 हजार से अधिक बसों के काफिले के साथ 33 लाख किलोमीटर के संचालन से लगभग 27 लाख से अधिक यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं समयबद्ध परिवहन सेवा प्रदान करता है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के दिशादर्शन में गुजरात राज्य परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) ने 182 नई बसों के लोकार्पण से जनसेवा प्रतिबद्धता में एक नया माइलस्टोन जोड़ा है। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी तथा परिवहन राज्य मंत्री श्री प्रवीण माली के करकमलों से राज्य के सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक यानी कुल 182 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर यात्रियों की सेवा के लिए प्रस्थान कराने का गौरवशाली समारोह बुधवार को गांधीनगर में आयोजित किया गया। समारोह में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक तथा पदाधिकारी

भी सहभागी हुए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने इन नई बसों के चालकों को सांकेतिक रूप से चाबी अर्पित की।

आम आदमी के लिए आवागमन का सरल माध्यम गुजरात एसटी निगम दैनिक 8 हजार से अधिक बसों के काफिले के साथ 33 लाख किलोमीटर का संचालन कर 27 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाने के लिए स्वच्छ, सुरक्षित एवं समयबद्ध बस सेवाएँ प्रदान करता है।

निगम विभिन्न तीज-त्योहारों तथा धार्मिक मेलों में अतिरिक्त बसों का संचालन कर राज्य की जनता को अपने परिवार के साथ तीज-त्योहार मनाने के लिए परिवहन सेवा-सुविधाएँ देता है।

राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष नई एसटी बसें खरीदने के लिए एसटी निगम को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अंतर्गत 2024-25 में 963 सुपर एक्सप्रेस, 550 गुर्जर नगरी, 100 स्लीपर बसें, 350 मीडी बसें सहित 1963 वाहन जनता की सेवा में समर्पित किए गए हैं।

पीपीपी आधार पर अत्याधुनिक 200 नई वॉल्वो तथा एसी बसों को भी संचालन में लाने का आयोजन किया गया है। समग्रतया 1963 नॉन-एसी तथा 200 एसी बसों को विभिन्न चरणों में जनता की सेवा में जोड़ा गया है। इनमें अब कुल 62 करोड़ रुपए के खर्च से इन 182 बसों को संचालन में लाने के लिए लोकार्पित किया गया है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों ने इस अवसर पर लोगों का अभिवादन कर उन्हें शुभकामनाएँ दीं। समारोह में परिवहन विभाग के प्रधान सचिव श्री हारित शुक्ला, परिवहन आयुक्त तथा जीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. राजेन्द्र कुमार और निगम के अधिकारी उपस्थित रहे।

सोना वायदा में 1616 रुपये और चांदी वायदा में 2112 रुपये की गिरावट: क्रूड ऑयल वायदा 60 रुपये फिसला

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 162094.92 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 28774.87 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 133320.04 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2560.48 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 16922.09 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 155658 रुपये के भाव पर खूलकर, 156075 रुपये के दिन के उच्च और 154201 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 155985 रुपये के पिछले बंद के सामने 1616 रुपये या 1.04 फीसदी गिरकर 154369 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा 1124 रुपये या 0.88 फीसदी गिरकर 126516 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 149 रुपये या 0.93 फीसदी गिरकर 15854 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी अप्रैल वायदा 155989 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 156156 रुपये और नीचे में 154306 रुपये पर पहुंचकर, 1653 रुपये या 1.06 फीसदी गिरकर 154377 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम 156833 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 156850 रुपये और नीचे में 155211 रुपये पर पहुंचकर, 156849 रुपये के पिछले बंद के सामने 1602 रुपये या 1.02 फीसदी गिरकर 155247 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 251498 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 254897 रुपये और नीचे में 249501 रुपये पर पहुंचकर, 253113 रुपये के पिछले बंद के सामने 2112 रुपये या 0.83 फीसदी गिरकर 251001 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 2940 रुपये या 1.13 फीसदी घटकर 256126 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 2646 रुपये या 1.02 फीसदी गिरकर 256506 रुपये प्रति

- कमोडिटी वायदाओं में 28774.87 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 133320.04 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 16922.09 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार

किलो के भाव पर पहुंचा।

मेटल वर्ग में 2390.14 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा 7.95 रुपये या 0.68 फीसदी गिरकर 1168.55 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता मार्च वायदा 2.2 रुपये या 0.69 फीसदी औंधकर 317.1 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 90 पैसे या 0.26 फीसदी की नरमी के साथ 340 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

जबकि सीसा मार्च वायदा 80 पैसे या 0.43 फीसदी टूटकर 187.15 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 8946.62 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 8771 रुपये के भाव पर खूलकर, 8896 रुपये के दिन के उच्च और 8501 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 60 रुपये या 0.68 फीसदी गिरकर 8811 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मार्च वायदा 47 रुपये या 0.53 फीसदी की गिरावट के साथ 8807 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा 277.5 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 278 रुपये और नीचे में 271.4 रुपये पर पहुंचकर, 280.9 रुपये के पिछले बंद के सामने 5 रुपये या 1.78 फीसदी गिरकर 275.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 5.1 रुपये या 1.81 फीसदी की गिरावट के साथ 276 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मार्च वायदा 968 रुपये पर खूलकर, 1.4 रुपये या 0.14 फीसदी औंधकर 966.2 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 10756.56 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 6165.54 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1593.99 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 440.17 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 4.85 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 349.26 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 7396.68 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1521.41 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 4.76 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 2.84 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 11265 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 63428 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 32461 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 474758 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 67362 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 6917 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 20853 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 79623 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 23995 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 31137 लोट के स्तर पर था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल अप्रैल 9000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 10.3 रुपये की गिरावट के साथ 929 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.85 रुपये की गिरावट के साथ 8.6 रुपये हुआ। सोना मार्च 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 355 रुपये की गिरावट के साथ 400 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1235 रुपये की गिरावट के साथ 8824.5 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3.47 रुपये की गिरावट के साथ 3.82 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 330 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 67 पैसे की नरमी के साथ 0.65 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल अप्रैल 7000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 14.1 रुपये की गिरावट के साथ 219.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.8 रुपये की बढ़त के साथ 7.65 रुपये हुआ।

सोना मार्च 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 281.5 रुपये की बढ़त के साथ 777 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 214.5 रुपये की बढ़त के साथ 576 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1150 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 92 पैसे के सुधार के साथ 7.54 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 315 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 64 पैसे के सुधार के साथ 2 रुपये हुआ।

स्पीपा के प्रशिक्षु अधिकारियों की गुजरात विधानसभा में अध्ययन यात्रा

विधानसभा की कार्यपद्धति की प्रत्यक्ष समझ के साथ मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष के साथ फोटो सेशन

(जीएनएस)। गांधीनगर : सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान (स्पीपा), अहमदाबाद द्वारा उसके गांधीनगर परिसर में चल रहे प्रथम कॉमन फाउंडेशन कोर्स अंतर्गत प्रशिक्षु अधिकारियों के अध्ययन के लिए स्पीपा के महानिदेशक श्री हारित शुक्ला के प्रेरक मार्गदर्शन में प्रशिक्षुओं की गुजरात विधानसभा में अध्ययन यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरे में लगभग 50 महिला प्रशिक्षु अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

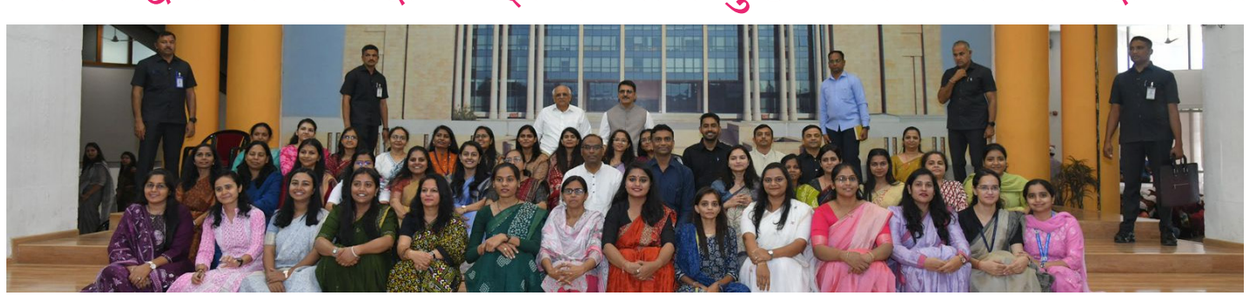

इस दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों ने विधानसभा के प्रश्नकाल का निरीक्षण कर राज्य की वैधानिक प्रक्रिया के व्यावहारिक पहलुओं की प्रत्यक्ष समझ प्राप्त की। इसके अलावा; विधानसभा के दैनिक कामकाज, चर्चा तथा निर्णय प्रक्रिया के बारे में भी उन्होंने मार्गदर्शन प्राप्त किया। यह उनके प्रशासनिक जीवन में उपयोगी सिद्ध होगा।

प्रशिक्षु अधिकारियों को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी के साथ समूह तसवीर खिंचवाने का अवसर मिला।

इस अध्ययन दौरे के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों ने मंत्री श्रीमती मनीषा वकील, श्री अर्जुन मोढवाडिया तथा श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला से मुलाकात की और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। मंत्रियों ने लोक सेवा क्षेत्र में जिम्मेदारी, पारदर्शिता तथा लोक हित को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया।

इस अध्ययन यात्रा द्वारा प्रशिक्षु अधिकारियों को राज्य के वैधानिक प्रशासन की कार्यपद्धति के बारे में जो व्यापक व प्रत्यक्ष समझ प्राप्त हुई है, वह भविष्य में उनके प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन में सहायक होगी।

19,20 और 21 मार्च की रात्री में मीठाखली अंडरपास अस्थायी रूप से बंद रहेगा

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा अहमदाबाद शहर में मीठाखली स्थित रेलवे अंडरब्रिज नं 12 के ऊपर से गुजरने वाली रेलवे ट्रैक पर आवश्यक मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाएगा। इस कार्य के अंतर्गत ट्रैक के नीचे एवं ऊपर के हिस्सों में पटरियों की स्ट्रेंथनिंग तथा जर्जर प्लेटों को हटाकर नई प्लेटों की स्थापना की जाएगी।

यह कार्य दिनांक 19, 20 एवं 21 मार्च, 2026 को केवल रात्रि अवधि (रात्रि 00:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक) के दौरान किया जाएगा।

उक्त अवधि के दौरान मीठाखली अंडरपास के दोनों प्रवेश एवं निकास मार्ग वाहन यातायात के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

ट्रैफिक डायवर्जन विवरण:

मीठाखली छः रास्ता की ओर से अंडरपास के माध्यम से आश्रम रोड जाने वाला ट्रैफिक मीठाखली गांव के रास्ते आश्रम रोड एवं अन्य मुख्य मार्गों की तरफ से जा सकेगा।

आश्रम रोड की ओर से आने वाला ट्रैफिक आश्रम रोड स्थित बुट्टासिंह महादेव एवं खोडियार माता मंदिर के पास से नवरंगपुरा क्रॉसिंग होते हुए मीठाखली छः रास्ता एवं अन्य मार्गों की ओर जा सकेगा।

सभी नागरिकों से अनुरोध है कि उपरोक्त अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।